बृजलाल एच.सी. बनाम  हरियाणा राज्य और अन्य

(जी. एस. सिंघवी, *न्यायमूर्ति*)

*जी.एस. सिंघवी* और एम.एल. *सिंघल, न्यायमूर्ति के समक्ष*

बृजलाल एच.सी. - *याचिकाकर्ता।*

*बनाम*

हरियाणा राज्य और अन्य - *उत्तरदाता।*

*सी.डब्ल्यू.पी.* 1996 *की सं.* 2704

5 अगस्त, 1996।

*भारत का संविधान, 1950* - अनुच्छेद *226/227* पंजाब पुलिस *नियम, 1934* - *नियम 13.5, 13.8 और 13.18* - *तदर्थ* पदोन्नति - खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण की गई पदोन्नति - विशुद्ध रूप *से तदर्थ और संयोग के आधार पर पदोन्नति* - *याचिकाकर्ता* ने बुनियादी मानदंडों को पूरा नहीं किया - प्रत्यावर्तित - प्रत्यावर्तन आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है - याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है।

उपर्युक्त नियमों के विश्लेषण से पता चलता है कि एक कांस्टेबल के पास पदोन्नति के दो चैनल हैं। उसे नियम 13.5 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर चयन ग्रेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। उन्हें नियम 13.8 के तहत हेड कांस्टेबल के रूप में भी पदोन्नत किया जा सकता है। चयन ग्रेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए नियम 13.5 (2) के तहत अंक दिए जाने आवश्यक हैं, बशर्ते उम्मीदवार नियम 12.16 (1) में निर्धारित शारीरिक फिटनेस के मानक को पूरा करता हो; वह सरल उर्दू वाक्य और अंग्रेजी अंक पढ़ और लिख सकते हैं और उनके चरित्र रोल में नैतिक कलंक वाली कोई प्रविष्टि नहीं है। नियम 13.5 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाले कांस्टेबलों के नाम सूची क में शामिल किए जाते हैं जिन्हें प्रत्येक पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाए रखा जाना अपेक्षित है और इस सूची में शामिल किए जा सकने वाले नामों की अधिकतम संख्या संबंधित जिले में ग्रेड की स्थापना का 10 प्रतिशत है। एक कांस्टेबल जिसे नियम 13.6 के तहत चयन ग्रेड कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया जाता है, नियम 13.5 (7) के अनुसार तीन साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहता है और आचरण और दक्षता के अनुकरणीय मानक को बनाए रखने में विफलता के मामले में उसे बिना किसी जांच के वापस कर दिया जा सकता है।

(पैरा 7)

अभिनिर्धारित किया, नियम 13.8 के तहत हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए एक कांस्टेबल को लोअर स्कूल कोर्स पास होना चाहिए। प्रत्येक जिले में पात्र कांस्टेबलों के नामों वाली सूची ग रखी जानी अपेक्षित है और इसका उपयोग हेड कांस्टेबलों के पदों पर पदोन्नति करने के लिए किया जाना है। हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति पर एक व्यक्ति को दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाना आवश्यक है। परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे परिवीक्षाधीन हेड कांस्टेबल को वापस कर सकता है। नियम 13.8 के दूसरे भाग में मुख्य नियम से एक अपवाद को शामिल किया गया है जो लोअर स्कूल कोर्स को पास करने को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए एक शर्त बनाता है। इस अपवाद के तहत, सक्षम प्राधिकारी लोअर स्कूल कोर्स पास किए बिना भी एक चयन ग्रेड कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत कर सकते हैं। हालांकि, यह शक्ति पूर्ण और निरंकुश है। बल्कि, यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है: -

(i) इस तरह की पदोन्नति केवल चयन ग्रेड कांस्टेबलों को दी जा सकती है, जिसका अर्थ है कि उम्मीदवार पहले से ही नियम 13.5 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा कर चुका है:

(ii) उसे अन्यथा इस तरह की पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है;

(iii) संबंधित रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक इस तरह की पदोन्नति को मंजूरी देते हैं; और

(iv) ऐसी पदोन्नति कुल रिक्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(पैरा 8)

अभिनिर्धारित किया कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने सक्षम अधिकारियों को उन लोगों में से 10 प्रतिशत पदोन्नति करने की शक्ति प्रदान की है, जिन्होंने लोअर स्कूल कोर्स पास नहीं किया है , यह महसूस करते हुए कि कुछ कांस्टेबल जो चयन ग्रेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए फिट पाए गए हैं, लेकिन वे लोअर स्कूल कोर्स को पास करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए, रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी कुल रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक पदोन्नति दे सकता है। इसलिए, यह मानना तर्कसंगत है कि कोई भी कांस्टेबल, जिसे चयन ग्रेड नहीं मिला है, को नियम 13.8 (2) के दूसरे भाग के तहत हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 9)

*मामले* के रिकॉर्ड से यह भी स्थापित होता है कि न तो पुलिस अधीक्षक, रेलवे और न ही पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे और संचालन ने आदेश जारी होने से पहले हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों के मामलों की जांच और विचार किया था। इसलिए, यह मानना उचित है कि याचिकाकर्ता की पदोन्नति नियम 13.8 (2) के तहत नहीं थी और उसे वरिष्ठ व्यक्तियों के दावों की अनदेखी करते हुए आकस्मिक पदोन्नति दी गई थी और इस तरह की पदोन्नति के आधार पर याचिकाकर्ता हेड कांस्टेबल के रूप में जारी रहने के लिए किसी भी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और न ही केवल इस आधार पर पुष्टि का दावा किया जा सकता है कि उसने दो साल से अधिक की अवधि के लिए हेड कांस्टेबल का पद संभाला था।

(पैरा 18)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एच एस मान।

प्रतिवादी के लिए रितु बाहरी, एएजी, हरियाणा।

बृजलाल एच.सी. बनाम  हरियाणा राज्य और अन्य

(जी. एस. सिंघवी, *न्यायमूर्ति*)

निर्णय

*जी. एस. सिंघवी, न्यायमूर्ति*

(1) यह याचिका अनुलग्नक पीएल के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया गया है और उसे कांस्टेबल के पद पर वापस भेज दिया गया है।

(2) याचिकाकर्ता 2 जनवरी, 1981 को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सेवा में शामिल हुए। उन्हें  पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे और संचालन, हरियाणा द्वारा जारी 5 जुलाई 1989 के आदेश अनुलग्नक पी 4 द्वारा तदर्थ आधार पर हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। वर्ष 1992 में याचिकाकर्ता ने 1992 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4765 को दायर किया, जिसमें हेड कांस्टेबल के पद से कांस्टेबल के पद पर उनकी वापसी को चुनौती दी गई। इस याचिका पर 1993 के सीडब्ल्यूपी संख्या 459 के साथ श्री बलबीर सिंह द्वारा दायर किया गया था, जिन्हें 8 दिसंबर, 1993 को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सहायक पुलिस उप निरीक्षक के पद से वापस कर दिया गया था। डिवीजन बेंच ने कहा कि पंजाब पुलिस की सवारी, जो राज्य या हरियाणा पर लागू होती है,  में *तदर्थ* पदोन्नति करने के लिए कई  व्यक्तियों को समय से पहले पदोन्नति देने का प्रावधान है। डिवीजन बेंच ने कहा कि सरकार को उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पदोन्नति प्रदान करने के लिए पंजाब पुलिस नियमों में उचित प्रावधान करना चाहिए या जिन्होंने निर्वहन या अपने कर्तव्यों में उत्कृष्टता दिखाई है और समय से पहले पदोन्नति का आदेश केवल पुलिस महानिदेशक द्वारा दिया जाना चाहिए और अन्य अधिकारियों को केवल पुलिस महानिदेशक को सिफारिश करनी चाहिए। साथ ही रिट याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं की ओर से अपील/संशोधन/स्मारक के रूप में मानने का निर्देश दिया गया था और पुलिस महानिदेशक को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के गुण-दोष की जांच करने के बाद इसका निपटान करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने पुलिस महानिदेशक के अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ता के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाने का भी आदेश दिया। इसके बाद,  पुलिस महानिदेशक द्वारा उनके अभ्यावेदन के निर्णय के आक्षेपित आदेश के तहत याचिकाकर्ता को अवगत करा दिया गया है, और उन्हें कांस्टेबल के पद पर वापस कर दिया गया है।

(3) याचिकाकर्ता ने मनमानी, दुर्भावना और विवेक का इस्तेमाल नहीं करने के *आधार पर प्रत्यावर्तन के आदेश पर सवाल उठाया* है  । उनका तर्क यह है कि पुलिस महानिदेशक ने ***रिशाल सिंह और अन्य* बनाम *हरियाणा राज्य*** *(1) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून की अनदेखी की* है*, साथ ही 1993 के सीडब्ल्यूपी संख्या 11586 में 20 सितंबर, 1994 को एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश,* हरदेन सिंह *बनाम हरियाणा राज्य इसलिए,* आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। यह भी अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता को खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति दी गई थी और हेड कांस्टेबल के रूप में काम करने के छह साल से अधिक की अवधि के बाद याचिकाकर्ता को वापस करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

(1)  जे.टी .1994 *(2)* एस.सी. 157।

प्रतिवादियों ने यह कहते हुए आक्षेपित प्रत्यावर्तन को उचित ठहराया है कि याचिकाकर्ता को दी गई पदोन्नति विशुद्ध रूप से *तदर्थ* और संयोग से थी और इस तरह के आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं मिला। उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता ने खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उनके अनुसार उनकी उपलब्धियां रेंज स्पोर्ट्स तक ही सीमित हैं। उत्तरदाताओं ने आगे कहा है कि पुलिस नियमों में *तदर्थ* पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है और चूंकि याचिकाकर्ता की पदोन्नति विशुद्ध रूप से संयोग से हुई थी, इसलिए प्रतिवादियों द्वारा उसके सेवा रिकॉर्ड और वरिष्ठ व्यक्तियों के दावे को ध्यान में रखते हुए उसे कांस्टेबल के पद पर वापस लाने में कोई अवैधता नहीं की गई थी।

(4) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हेड कांस्टेबल के पद पर तदर्थ *पदोन्नति के लिए पंजाब पुलिस नियमों में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण* , 5 जुलाई, 1989 को पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा आदेश ति हेड कांस्टेबल के रूप में याचिकाकर्ता की पदोन्नति को एक वास्तविक पदोन्नति के रूप में माना जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को दो साल की परिवीक्षा की समाप्ति पर एक पक्का हेड कांस्टेबल माना जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भले ही पदोन्नति का आदेश अनुलग्नक पी 4 नियमों के नियम 13.8 (2) का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन *रिशाल सिंह के मामले* (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए याचिकाकर्ता की पदोन्नति को खेल कोटा के खिलाफ माना जाना चाहिए। विद्वान वकील ने अनुलग्नक पी 5 और अनुलग्नक पी 6 पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिन्हें 3 जुलाई, 1996 को विविध आवेदन के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया था और प्रस्तुत किया गया था कि पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, उत्कृष्ट खिलाड़ियों / महिलाओं के लिए पदोन्नति के लिए 2 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाने हैं। विद्वान वकील के अनुसार इन निर्देशों को पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 7 के तहत जारी किया गया माना जाएगा। श्री मान ने यह भी तर्क दिया कि शीर्ष अदालत और इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए याचिकाकर्ता को समान लाभ नहीं देने का कोई कारण या औचित्य नहीं हो सकता है। सहायक महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड को उसकी सेवा फाइल और जिला जीआरपी के कांस्टेबलों की वरिष्ठता सूची के साथ पेश किया, जिसे पुलिस अधीक्षक, रेलवे, हरियाणा, अंबाला छावनी द्वारा तैयार किया गया था और बताया कि याचिकाकर्ता का नाम सीनियर नंबर 249 पर दिखाई देता है और वह एक उन्नत कांस्टेबल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता से वरिष्ठ कम से कम 30 व्यक्ति अभी भी हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब उन्हें 5 जुलाई, 1989 को *तदर्थ* और भाग्यशाली पदोन्नति दी गई थी। विद्वान सहायक महाधिवक्ता के अनुसार, यह किसी अन्य व्यक्ति के मामले पर विचार किए बिना किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को दी गई विशुद्ध रूप से आकस्मिक पदोन्नति के आधार पर उन्होंने विशेष रूप से हेड कांस्टेबल के पद को धारण करने का कोई अधिकार हासिल नहीं किया। जब उसने लोअर स्कूल कोर्स पास नहीं किया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार बन सकता है। सहायक महाधिवक्ता ने हमारे समक्ष हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा हरियाणा सशस्त्र पुलिस-सह-सीएसओ, मधुबन के उप महानिरीक्षक को लिखे गए पत्र संख्या 9632 टी 3 दिनांक 11 नवंबर, 1982 का एक फोटोस्टेट प्रति भी हमारे सामने रखा। इस पत्र के साथ हरियाणा पुलिस खेल संविधान की प्रति संबंधित अधिकारी को भेजी गई। हरियाणा पुलिस खेल संविधान के नियमों से, विद्वान एएजी ने बताया कि विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया खिलाड़ी ही पदोन्नति और पदोन्नति पाठ्यक्रम के लिए विशेष ध्यान देने का हकदार है। उन्होंने आगे एक बयान दिया कि सरकार

द्वारा मेधावी खिलाड़ियों के लिए हेड कांस्टेबल के पदों के लिए आरक्षण करने के लिए कोई अन्य निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(5) पंजाब पुलिस नियमों के अध्याय 13 जैसा कि वे हरियाणा राज्य पर लागू होते हैं, में पदोन्नति के प्रावधान हैं। नियमों के नियम 13.1 में कहा गया है कि एक रैंक से दूसरे रैंक पर और एक ही रैंक में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति वरिष्ठता और दक्षता के साथ-साथ ईमानदारी द्वारा चयन द्वारा की जाएगी, जो चयन को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक होंगे। यह भी कहा गया है कि प्रत्येक मामले में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या व्यावहारिक अनुभव जैसी विशेष योग्यताओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। नियम 13.1(3) में नामांकित पुलिस अधिकारियों के बीच पदोन्नति को विनियमित करने के उद्देश्य से सूची ए, बी, सी, डी, ई और एफ को बनाए रखने की परिकल्पना की गई है। सूची ए, बी, सी, डी को प्रत्येक जिले में बनाए रखने योग्य होना आवश्यक है और इनका उपयोग कांस्टेबलों के चयन ग्रेड और हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षकों के रैंक पर पदोन्नति करने के लिए किया जाना है। सूची ई को पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय में बनाए रखा जाना आवश्यक है और इस सूची का उपयोग उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति करने के लिए किया जाना है। सूची एफ को महानिरीक्षक के कार्यालय में बनाए रखा जाना आवश्यक है और इसका उपयोग निरीक्षक के पद पर पदोन्नति करने के लिए किया जाना है। नियम 13.2 में वेतन वृद्धि प्रदान करने और उसे रोकने का प्रावधान है। नियम 13.3 पदोन्नति करने के लिए सक्षम विभिन्न प्राधिकरणों को निर्दिष्ट करता है। नियम 13.4 में कार्यवाहक पदोन्नति की बात कही गई है। नियम 13.4(1) के अनुसार रेलवे के उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस को निरीक्षक के पद पर कार्यवाहक पदोन्नति करने का अधिकार प्राप्त है। उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक के पद पर ऐसी पदोन्नति पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा नियम 13.4 (2) के अनुसार की जा सकती है। नियम 13.4 (3) के अनुसार ऊपरी अधीनस्थों की सभी कार्यवाहक पदोन्नतियों को पुलिस राजपत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। नियम 13.5 कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में पदोन्नति से संबंधित है। इसमें कांस्टेबलों के चयन ग्रेड के लिए प्रोमोशन के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। नियम 13-5(2) विभिन्न शीर्षकों के तहत अंक निर्धारित करता है जिसके आधार पर प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए अंकों के आधार पर निर्धारित योग्यता का मूल्यांकन, कांस्टेबल के चयन ग्रेड में पदोन्नति की जानी है नियम 13.6 कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में पदोन्नति के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के स्तर पर सूची ए की तैयारी पर विचार करता है। नियम 13.7 सूची बी को संदर्भित करता है जिसे पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक है। इस सूची में पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में कांस्टेबलों के पदोन्नति पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयनित कांस्टेबलों के नाम थे। नियम 13.8 (1) में यह आवश्यक है कि उन कांस्टेबलों के कार्ड इंडेक्स फॉर्म में एक सूची रखी जाएगी जिन्होंने लोअर स्कूल कोर्स पास किया है और जिन्हें हेड कांस्टेबल में पदोन्नति के लिए पात्र माना जाता है। नियम 13.8 (2) में नियम 13.1 (1) और (2) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। इस उप-नियम का दूसरा भाग पुलिस उप महानिरीक्षक को उन लोगों में से अधिकतम 10 प्रतिशत रिक्तियों तक चयन ग्रेड कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत करने का अधिकार देता है, जिन्होंने लोअर स्कूल कोर्स पास नहीं किया है, लेकिन अन्यथा पदोन्नति के उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। नियम 13.8-ए 'सूचियों' ए, बी या सी में नियुक्ति या पेंशन के लिए इन योग्यताओं को निर्धारित करता है। नियम 13.9 और 13.10 सूची डी और ई से संबंधित हैं। नियम 13.18 को छोड़कर अध्याय 13 के ये नियम और

अन्य उपधाराएं। 13.19 और 13.20 इस मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

(6) नियम 13.18 परिवीक्षा की अवधि निर्दिष्ट करता है। नियम 13.19 में राष्ट्रपति पुलिस और अग्निशमन सेवा पदक प्राप्त करने वाले कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत करने के लिए विशेष प्रावधान है। नियम 13.20 में नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों के गठन की परिकल्पना की गई है। प्रतिद्वन्दी तर्कों की बेहतर समझ के लिए इन नियमों की धारा 13.1, 13: 2, 13.5 13.6, 13.7(1), 13.8, 13.18, 13.19 और 13.20 को पुन: पेश करना उचित समझते हैं।

> "13.1. (1) एक रैंक से दूसरे रैंक पर और एक ही रैंक में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति, वरिष्ठता द्वारा छेड़छाड़ किए गए चयन द्वारा की जाएगी। दक्षता और ईमानदारी चयन को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक होंगे। विशिष्ट योग्यता, चाहे उत्तीर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रकृति में हो या व्यावहारिक अनुभव, प्रत्येक मामले में सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। जब दो अधिकारियों की योग्यता अन्यथा समान होती है, तो वरिष्ठ को पदोन्नत किया जाएगा। यह नियम समय-पैमाने के भीतर वेतन वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है।
>
> (2) पुलिस बल के वर्तमान संविधान के तहत किसी भी निचले अधीनस्थ को आमतौर पर जांच के स्वतंत्र संचालन या पुलिस स्टेशन या इसी तरह की इकाई का स्वतंत्र प्रभार नहीं सौंपा जाएगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि उच्च अधीनस्थ रैंक की जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए आवश्यक विशेषताओं वाले अच्छी तरह से शिक्षित कांस्टेबलों को त्वरित पदोन्नति प्राप्त करनी चाहिए ताकि वे जल्द से जल्द उस रैंक तक पहुंच सकें, जैसे ही वे निर्धारित पाठ्यक्रमों को पास कर लेते हैं, और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के रैंक में परीक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
>
> (3) नामांकित पुलिस अधिकारियों के बीच पदोन्नति को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए छह पदोन्नति सूचियां - ए, बी, सी, डी, ई और एफ बनाए रखी जाएंगी।
>
> नियम 13.6, 13.7, 13.8 और 13.9 में निर्धारित प्रत्येक जिले में सूची ए, बी, सी और डी बनाए रखी जाएगी और कांस्टेबलों के चयन ग्रेड और हेड कांस्टेबल और सहायक उप-निरीक्षक के रैंक पर पदोन्नति को विनियमित करेगी। सूची ई उप-नियम 13.10 (1) में निर्धारित उप महानिरीक्षक के कार्यालय में रखी जाएगी और उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को विनियमित करेगी। सूची एफ को उप नियम 13.15 (1) में निर्धारित महानिरीक्षक के कार्यालय में बनाए रखा जाएगा और निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को विनियमित करेगा।
>
> आदेश में कहा गया है, 'ए, बी, सी, डी या ई सूचियों में प्रविष्टि या हटाने को ऑर्डर बुक और संबंधित पुलिस अधिकारी के चरित्र रोल में दर्ज किया जाएगा। ये सूचियां उन अधिकारियों की नाममात्र की सूचियां हैं जिनके प्रवेश को अधिकृत किया गया है। चरित्र रोल की सावधानीपूर्वक जांच के बिना कोई वास्तविक चयन नहीं किया जाएगा।

बृजलाल एच.सी. बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(जी. एस. सिंघवी, *न्यायमूर्ति*)

"13.2. *वेतन वृद्धि प्रदान करने की शक्ति-* अधीक्षकों द्वारा सभी ऊपरी और निचले अधीनस्थों को वेतन की वृद्धि दी जाएगी, बशर्ते कि अध्याय XVI में निहित नियमों के अनुसार एक वेतन वृद्धि को औपचारिक दंड के रूप में रोका जा सकता है। वेतन वृद्धि रोकने को कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के मामले में और पुलिस राजपत्र में प्रकाशित निरीक्षकों, सार्जेंट, उप-निरीक्षकों और सहायक उप-निरीक्षकों के मामले में आदेश पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। लिपिक संवर्ग के सदस्यों के मामले में, वेतन वृद्धि संबंधित कार्यालय के प्रमुख द्वारा प्रत्येक मामले में औपचारिक आदेश द्वारा दी जाएगी या रोकी जाएगी। जब किसी दक्षता सीमा को समय-पैमाने में किसी भी चरण या चरण में रखा जाता है, तो इसे केवल संबंधित समय-पैमाने में वृद्धि को रोकने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा एक विशिष्ट आदेश के अधिकार पर पारित किया जाएगा। सार्जेंट और उप-निरीक्षकों के मामले में क्रमशः महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक की रेत की आवश्यकता होती है।

13.5. कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में पदोन्नति:

1. किसी भी कांस्टेबल को कांस्टेबल के चयन ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह (ए) शारीरिक रूप से आवश्यक मानक (उप-नियम 12.16 (1)) तक नहीं पहुंच ता है, (बी) सरल उर्दू वाक्य और अंग्रेजी अंक पढ़ और लिख सकता है और (सी) नैतिक कलंक वाले किसी भी प्रविष्टि से स्पष्ट चरित्र रोल नहीं है। शर्त (क) को पुलिस अधीक्षकों द्वारा अच्छे कारणों के लिए शिथिल किया जा सकता है और शर्तों (ख) और (ग) में उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा छूट दी जा सकती है।

(2) उपनियम (1) में निर्धारित आवश्यक अर्हताएं रखने वाले पुरुषों को निम्नलिखित प्रणाली पर अंकन के क्रम के अनुसार रिक्तियों के रूप में पदोन्नत किया जाएगा: –

(ए) शिक्षा -

| | |
|---|---|
| एफए या उच्चतर | 5 अंक |
| मैट्रिक | 3 अंक |
| गैर-मैट्रिक लेकिन प्राथमिक से ऊपर | 2 अंक |

(बी) पाठ्यक्रम पारित—

| | |
|---|---|
| (i) लोअर स्कूल | 5 अंक |
| (ii) पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में ड्रिल | 3 अंक |
| (iii) यातायात (एक अनुमोदित मानक द्वारा) | 2 अंक |
| (iv) फिंगर प्रिंट | 2 अंक |
| (V) भर्ती परीक्षा में प्रथम या द्वितीय | 1 अंक |
| (vi) सेंट जॉन्स एम्बुलेंस प्रथम सहायता पाठ्यक्रम | 1 अंक |

| | |
|---|---|
| (vii) आर्मरर का कोर्स | 2 अंक |
| (सी) व्यावसायिक क्षमता | अधिकतम 12 अंकों तक। |
| (डी) चरित्र | अधिकतम 10 अंकों तक। |

(3) उप-नियम (2) में (सी) और (डी) के तहत पूर्ण अंक दस साल से कम सेवा वाले कांस्टेबल को नहीं दिए जाएंगे।

(C) के अंतर्गत अंकन का अनुमान प्रशस्ति पत्रों और जासूसी कार्य, विघटन, आसूचना कर्तव्य आदि में विशेष योग्यता के अन्य प्रमाणों द्वारा लगाया जाएगा।

चित्रण- ए, जिसने पहली कला परीक्षा उत्तीर्ण की है, अपने भर्ती पाठ्यक्रम में प्रथम है, यातायात और फिंगर प्रिंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, तीन साल की सेवा की है और सहायक पुलिस स्टेशन क्लर्क का काम सीखा है, उसके पास 16 अंक हो सकते हैं। बी, 24 साल की सेवा का एक अर्ध-अनपढ़ कांस्टेबल, जिसके पास 18 प्रशंसा प्रमाण पत्र, एक स्पष्ट रोल और छायांकन कार्य में स्थापित विश्वसनीयता है, को केवल (सी) और (डी) के तहत 22 अंक प्राप्त हो सकते हैं।

(4) उप-नियम (2) में वर्णित अंकन प्रणाली के बावजूद, प्रशिक्षकों, स्थायी यातायात कर्मचारियों, पुलिस स्टेशनों में लिपिक यी नियुक्तियों, मुख्यालय, गुप्त सेवा और केंद्रीय जांच एजेंसी ड्यूटी जैसे कठिन और जिम्मेदार ड्यूटी पर तैनात पुरुषों को चयन ग्रेड में अस्थायी पदोन्नति दी जा सकती है। केवल इन आधारों पर पदोन्नत किए गए पुरुषों को किसी भी समय समय-पैमाने पर वापस कर दिया जाएगा यदि वे उस कर्तव्य पर संतुष्टि देने में विफल रहते हैं जिसके लिए उन्हें पदोन्नत किया गया है या तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए ऐसी ड्यूटी से हटा दिया गया है।

(5) शिक्षा के मैट्रिक मानक और उससे ऊपर के कांस्टेबलों और असाधारण पारिवारिक दावों वाले कांस्टेबलों को उप-नियम (2) में वर्णित अंकन प्रणाली के बावजूद, क्रेडिट के साथ अपने भर्ती पाठ्यक्रम को पास करने के तुरंत बाद चयन ग्रेड में पदोन्नत किया जा सकता है। इस ग्रेड में सीधी नियुक्ति नियम 12.10-ए के अनुसार की जाती है।

(6) इस नियम में निर्धारित अंकन प्रणाली को बनाए रखने के लिए प्रत्येक कांस्टेबल के चरित्र रोल के साथ फॉर्म 13,5 (6) में एक शीट संलग्न की जाएगी।

(7) चयन ग्रेड में पदोन्नति तीन साल के लिए परिवीक्षा पर होगी और इस तरह पदोन्नत कांस्टेबलों को उनकी ऐसी पदोन्नति के तीन वर्षों के दौरान या समाप्ति पर औपचारिक विभागीय कार्यवाही के बिना वापस किया जा सकता है यदि वे आचरण और दक्षता के अनुकरणीय मानक को बनाए रखने में विफल रहते हैं। इस तरह के प्रत्यावर्तन स्वतंत्र रूप से किए जाएंगे।

(8) एक बार इसमें पुष्टि होने के बाद चयन ग्रेड परिवर्तन से हटाने में औपचारिक कार्यवाही शामिल होती है। चयन ग्रेड कांस्टेबल के मामले में, जिसे न्यायिक रूप से जुर्माना या

केवल कारावास, या दोनों, या एक महीने से अधिक के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है, पुलिस नियम 16.2 (2) के तहत खारिज नहीं किया जाता है, सामान्य न्यूनतम विभागीय सजा को समय-पैमाने तक कम कर दिया जाएगा। इसी तरह, अक्षमता के दोषी पाए गए चयन ग्रेड कांस्टेबल के मामले में, चाहे सामान्य रूप से या विशेष योग्यता के संबंध में, जिसके लिए पदोन्नति दी गई है, सामान्य न्यूनतम सजा को समय-पैमाने तक कम किया जाएगा।

"13.6 सूची ए। *कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में पदोन्नति।* कांस्टेबलों के चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए नियम 13.5 के तहत पात्र कांस्टेबलों की सूची ए (फार्म 13.6 में) का अनुरक्षण प्रत्येक पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के तहत किया जाएगा। सूची में नामों की संख्या जिले में ग्रेड की स्थापना के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

"13.7 (1) चयन ग्रेड कांस्टेबलों को पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के रूप में उपयुक्त माना जाता है।

"13.8 *सूची सी. हेड कांस्टेबलों को पदोन्नति।*

(1) प्रत्येक जिले में उन सभी कांस्टेबलों की सूची कार्ड अनुक्रमणिका रूप (प्रपत्र 13.8(1)) में रखी जाएगी जिन्होंने फिल्लौर में लोअर स्कूल कोर्स उत्तीर्ण किया है और जिन्हें हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र माना जाता है। सूची में शामिल प्रत्येक कांस्टेबल के लिए एक कार्ड तैयार किया जाएगा और इसमें उप-नियम 13.5 (2) के तहत उसका अंकन और अधीक्षक द्वारा स्वयं नोट होंगे, या राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके तहत कांस्टेबल ने काम किया है, उनकी योग्यता और चरित्र पर। सूची अधीक्षक द्वारा गोपनीय रूप से रखी जाएगी और पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अपने वार्षिक, निरीक्षण में जांच और अनुमोदित किया जाएगा।.

(2) हेड कांस्टेबल को पदोन्नति उप-नियम 13.1 (1) और (2) में वर्णित सिद्धांत के अनुसार की जाएगी। सूची सी में प्रवेश की तारीख भौतिक नहीं होगी, लेकिन योग्यता की तुलना करते समय योग्यता के क्रम को ध्यान में रखा जाएगा जिसमें परीक्षाएं उत्तीर्ण की गई हैं। ऐसे मामलों में जहां अन्य योग्यताएं समान हैं, पुलिस बल में वरिष्ठता निर्णायक कारक होगी। जिन सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबलों ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में लोअर स्कूल कोर्स पास नहीं किया है, लेकिन अन्यथा उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें उप महानिरीक्षक की मंजूरी से अधिकतम दस प्रतिशत रिक्तियों तक हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है।

"13.18. रैंक में पदोन्नत सभी पुलिस अधिकारी दो साल के लिए परिवीक्षा पर होंगे, बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक मामले में एक विशेष आदेश द्वारा, परिवीक्षा की अवधि के लिए कार्यवाहक सेवा की अवधि की गणना करने की अनुमति दे सकता है। परिवीक्षाधीन अवधि की समाप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी या तो परिवीक्षाधीन की पुष्टि कर सकता है या उसे वापस कर सकता है, या, यदि वह उचित समझता है, तो परिवीक्षा की अवधि को कुल मिलाकर एक वर्ष तक बढ़ा सकता है और परिवीक्षा की

विस्तारित अवधि के समापन पर, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो परिवीक्षा की मूल अवधि के समापन पर पारित किया जा सकता था। परिवीक्षा पर रहते हुए, अधिकारियों को वापस किया जा सकता है या विभागीय कार्यवाही के बिना उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है। इस तरह के प्रत्यावर्तन को नियम 16.4 के प्रयोजनों के लिए रैंक में कमी नहीं माना जाएगा। यह नियम चयन ग्रेड में पदोन्नत कांस्टेबल और उप-निरीक्षकों पर लागू नहीं होगा, जिनके मामले नियम 13.5 और 13.14 द्वारा शासित होते हैं।

"13.19. राष्ट्रपति के पुलिस और अग्निशमन सेवा पदक और पुलिस पदक के प्राप्तकर्ता को विशेष पदोन्नति।

(1) राष्ट्रपति के पुलिस और अग्निशमन सेवा पदक का पुरस्कार प्राप्त करने वाले कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल की पहली मूल रिक्ति में पदोन्नत किया जाएगा, जो उस जिले में होता है जिसमें वह पदक राजपत्रित होने के बाद सेवारत है।

(2) पुलिस पदक से सम्मानित कांस्टेबल, यदि पहले से ही चयन ग्रेड में नहीं है, तो उसे नियम 13.5 (7) में निर्धारित परिवीक्षा पर उस ग्रेड में पदोन्नत किया जाएगा।

(3) उक्त नियमों में, नियम 13.19 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

यह सुनिश्चित करने के लिए कि चयन और पदोन्नति नियमों के अनुसार की जाती है, विभागीय पदोन्नति समितियां। (जारी रखें 3) ।

"13.20. पदोन्नति समितियां।

विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति समितियों का गठन किया जाएगा। ऐसी समितियां सभी पात्र व्यक्तियों को लिखित परीक्षा और परेड के माध्यम से रखने की व्यवस्था करेंगी। इसके बाद योग्यता अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का उक्त समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। समिति ऐसे व्यक्तियों की योग्यता का आकलन उनके सेवा रिकॉर्ड के साथ-साथ परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर करेगी। विभिन्न परीक्षणों के लिए पाठ्यक्रम, अंकों का अर्हक प्रतिशत, विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना पुलिस महानिरीक्षक द्वारा एक स्थायी आदेश के रूप में निर्धारित की जाएगी।

(7) उपर्युक्त नियमों के विश्लेषण से पता चलता है कि एक कांस्टेबल के पास पदोन्नति के दो चैनल हैं। उसे नियम 13.5 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर चयन ग्रेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। उन्हें नियम 13.8 के तहत हेड कांस्टेबल के रूप में भी पदोन्नत किया जा सकता है। चयन ग्रेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए नियम 13.5 (2) के तहत अंक दिए जाने आवश्यक हैं, बशर्ते उम्मीदवार नियम 12.16 (1) में निर्धारित शारीरिक फिटनेस के मानक को पूरा करता हो; वह सरल उर्दू वाक्य और अंग्रेजी अंक पढ़ और लिख सकते हैं और उनके चरित्र रोल में नैतिक कलंक वाली कोई प्रविष्टि नहीं है। नियम 13.5 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाले कांस्टेबलों के नाम सूची क में शामिल किए जाते हैं जिन्हें प्रत्येक पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाए रखा जाना अपेक्षित है और इस सूची में शामिल किए जा सकने वाले नामों की अधिकतम संख्या संबंधित जिले में ग्रेड की स्थापना का 10 प्रतिशत है। एक कांस्टेबल जिसे नियम 13.6 के तहत चयन ग्रेड कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया जाता है,

नियम 13.5 (7) के अनुसार तीन साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहता है और आचरण और दक्षता के अनुकरणीय मानक को बनाए रखने में विफलता के मामले में उसे बिना किसी जांच के वापस कर दिया जा सकता है।

(8) नियम 13.8 के तहत हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए एक कांस्टेबल को लोअर स्कूल कोर्स पास होना चाहिए। प्रत्येक जिले में पात्र कांस्टेबलों के नामों वाली सूची ग रखी जानी अपेक्षित है और इसका उपयोग हेड कांस्टेबलों के पदों पर पदोन्नति करने के लिए किया जाना है। हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति पर एक व्यक्ति को दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाना आवश्यक है। परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे परिवीक्षाधीन हेड कांस्टेबल को वापस कर सकता है। नियम 13.8 के दूसरे भाग में मुख्य नियम से एक अपवाद को शामिल किया गया है जो लोअर स्कूल कोर्स को पास करने को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए एक शर्त बनाता है। इस अपवाद के तहत, सक्षम प्राधिकारी लोअर स्कूल कोर्स पास किए बिना भी एक चयन ग्रेड कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत कर सकते हैं। हालांकि, यह शक्ति पूर्ण और निरंकुश है। बल्कि, यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है: -

(i) इस तरह की पदोन्नति केवल चयन ग्रेड कांस्टेबलों को दी जा सकती है, जिसका अर्थ है कि उम्मीदवार पहले से ही नियम 13.5 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा कर चुका है:

(ii) उसे अन्यथा इस तरह की पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है;

(iii) संबंधित रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक इस तरह की पदोन्नति को मंजूरी देते हैं; और

(iv) ऐसी पदोन्नति कुल रिक्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(9) हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने सक्षम प्राधिकारियों को लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं करने वालों में से 10 प्रतिशत पदोन्नति करने की शक्ति प्रदान की है, यह महसूस करते हुए कि कुछ कांस्टेबल जो चयन ग्रेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए हैं, लेकिन वे लोअर स्कूल पाठ्यक्रम को पास करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए, रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी कुल रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक पदोन्नति दे सकता है। इसलिए, यह मानना तर्कसंगत है कि कोई भी कांस्टेबल, जिसे चयन ग्रेड नहीं मिला है, को नियम 13.8 (2) के दूसरे भाग के तहत हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है।

(10) अब देखना यह है कि याचिकाकर्ता के मामले में उपरोक्त शर्तों को पूरा किया गया है या नहीं। अदालत के समक्ष पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि पुलिस अधीक्षक, रेलवे, हरियाणा, अंबाला छावनी ने 17 जून, 1989 को पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे और संचालन, हरियाणा को संबोधित पत्र के *माध्यम से* याचिकाकर्ता को हेड कांस्टेबल के पद पर *तदर्थ*पदोन्नति देने के लिए सिफारिशें की

थीं । उस पत्र में पुलिस अधीक्षक ने इंटर रेंज पुलिस खेलों में याचिकाकर्ता के प्रदर्शन का उल्लेख किया था। पुलिस उप महानिरीक्षक ने 5 जुलाई, 1989 को अनुलग्नक पी4 जारी किया जिसमें याचिकाकर्ता को *तदर्थ आधार पर हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया,* जिसमें स्पष्ट संकेत दिया गया कि यह पूरी तरह से अस्थायी और संयोग से पदोन्नति थी और उस आधार पर याचिकाकर्ता को अपने वरिष्ठों पर वरिष्ठता आदि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा और वह कारण बताओ नोटिस आदि के बिना प्रत्यावर्तित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

(11) न तो आदेश, अनुबंध पी 4, न ही रिट याचिका में किए गए कथन और न ही हमारे सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को किसी भी समय सेवा में प्रवेश के बाद चयन ग्रेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। सहायक महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कांस्टेबलों की सूची में 443 कांस्टेबलों के नाम शामिल हैं। याचिकाकर्ता का नाम सीनियर नंबर 207 पर दिखाई देता है। क्रम संख्या 184 तक कांस्टेबल हैं जिन्हें अपग्रेड कांस्टेबल के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रकार हमारे सामने दलीलों या दस्तावेजों के रूप में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि याचिकाकर्ता को चयन ग्रेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था और इसलिए, 5 जुलाई, 1989 के आदेश के तहत उसकी पदोन्नति को नियम 13.8 (2) के तहत किए गए के रूप में माना जाना चाहिए। हमारी राय में, याचिकाकर्ता, जिसे नियम 13.5 के तहत मानदंडों को पूरा करने पर चयन ग्रेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था, 10 प्रतिशत रिक्तियों के खिलाफ नियम 13.8 के तहत पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए भी पात्र नहीं था और वास्तव में पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे और संचालन ने नियम 13.8 (2) के तहत उनकी पदोन्नति का आदेश नहीं दिया था। इस चर्चा के तार्किक परिणाम के रूप में, यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को दी गई *तदर्थ* और भाग्यशाली पदोन्नति, दिनांक 5 जुलाई, 1989 के आदेश के तहत भूमिका 13.8 (2) के तहत नियमित पदोन्नति के रूप में नहीं माना जा सकता है और याचिकाकर्ता को 5 जुलाई, 1989 से परिवीक्षा पर हेड कांस्टेबल के रूप में नहीं माना जा सकता है और यह घोषित करना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ता ने दो साल की अवधि की समाप्ति पर हेड कांस्टेबल का दर्जा प्राप्त किया है।

(12) इस मुद्दे की दूसरे दृष्टिकोण से जांच किए जाने की आवश्यकता है। पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश करते समय, पुलिस अधीक्षक रेलवे ने किसी अन्य कांस्टेबल के मामले पर विचार नहीं किया। उन्होंने खेलों में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर *तदर्थ* पदोन्नति के लिए कई वरिष्ठ कांस्टेबलों के मामलों की जांच नहीं की। अपनी ओर से, पुलिस उप महानिरीक्षक ने अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों की उपलब्धियों की कोई जांच नहीं की। उन्होंने बस पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दे दी और 5 जुलाई, 1989 को आदेश जारी किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को वरिष्ठ व्यक्तियों के दावों पर विचार किए बिना तदर्थ पदोन्नति दी गई थी, जिनके पास उनके श्रेय के समान उपलब्धियां हो सकती हैं। इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता की पदोन्नति को तदर्थ और संयोग के रूप में वर्णित किया गया है जो उसे वरिष्ठ व्यक्तियों पर कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है, इस प्रकार

याचिकाकर्ता की याचिका कि उसे मूल हेड कांस्टेबल के रूप में माना जाना चाहिए, खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(13) अब हम विद्वान अधिवक्ता की इस दलील पर विचार करेंगे कि याचिकाकर्ता की पदोन्नति को खेल कोटा के खिलाफ माना जाना चाहिए और उस आधार पर, उसे मूल हेड कांस्टेबल के रूप में माना जाना चाहिए। नियम 13.8(2) में खिलाड़ियों के लिए विशेष कोटा का कोई उल्लेख नहीं है। अधिवक्ता चाहते थे कि हम नियम 13.8 (2) में अंतर को भरने के लिए सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों के रूप में अनुलग्नक पी 5 और पी 6 को पढ़ें। हम उनसे सहमत नहीं हैं कि इन दो दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्ता की पदोन्नति को खेल कोटा के खिलाफ नियमित पदोन्नति के रूप में माना जा सकता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अनुलग्नक पी.5 दिनांक 18 अगस्त, 1992 का है और अनुलग्नक पी6 दिनांक 31 अगस्त, 1992 का है। इन दोनों दस्तावेजों से पता चलता है कि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्कृष्ट खिलाड़ियों/महिलाओं के लिए पदोन्नति में 2 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, अनुलग्नक पी5 और पी 6 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि पुलिस अधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णय को सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसलिए, यह अत्यंत संदिग्ध है कि क्या ऐसे अनुदेशों को सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के रूप में माना जा सकता है और हेड कांस्टेबलों के पदों पर पदोन्नति करते समय इसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि हम यह मान भी लें कि अनुलग्नक पी 5 और पी6 में सरकार का प्रशासनिक निर्णय है, तो भी ऐसा निर्णय केवल 18 अगस्त, 1992 के बाद की गई पदोन्नतियों के संबंध में प्रभावी बनाया जा सकता है। बेशक, याचिकाकर्ता को इन निर्देशों के जारी होने से तीन साल पहले पदोन्नत किया गया था और इसलिए, अनुबंध पी 5 और पी 6 के आधार पर, याचिकाकर्ता की पदोन्नति को खिलाड़ियों के लिए आरक्षित 2 प्रतिशत पदों के खिलाफ नहीं माना जा सकता है।

(14) रिशाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त) मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला *और साथ ही हरदेन सिंह* बनाम हरियाणा *राज्य* (उपर्युक्त) मामले *में विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय,* किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करता है। *रिशाल सिंह* के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने दलील दी थी कि उनकी पदोन्नति नियम 13.8 (2) के तहत निर्धारित 10 प्रतिशत कोटा के भीतर थी और उनकी पदोन्नति नियमित आधार पर थी, भले ही इसे अस्थायी और तदर्थ आधार पर वर्णित किया गया था । प्रतिवादियों की ओर से, यह दलील दी गई थी कि अपीलकर्ता 35 वर्ष से कम आयु का नहीं था और इसलिए, वह नियम 13.0 (7) और नियम 13.8 (2) पर जवाब देने का हकदार नहीं था। न्यायमूर्तियो ने कहा कि अपीलकर्ता को खेल कोटा में माना गया था और नियम 13.8 (2) के अनुसार उपयुक्त पाया गया था और इसलिए, उसकी पदोन्नति को नियमित आधार पर माना जाना चाहिए, न कि तदर्थ *आधार पर।* हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों ने इस धारणा पर कार्रवाई की थी कि

अपीलकर्ता रिशाल सिंह को नियम 13.5 के अनुसार चयन ग्रेड पहले ही दिया जा चुका है। नियम 13.6 और चयन ग्रेड कांस्टेबल के रूप में उनकी उम्मीदवारी को 10 प्रतिशत कोटा के खिलाफ पदोन्नति के लिए माना गया था। *हरदेन सिंह के मामले में* वीके झांजी, जे. ने रिशाल सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए प्रत्यावर्तन के आदेश को रद्द कर दिया। उस फैसले के पैरा 3 से पता चलता है कि लिखित बयान में, उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया था कि याचिकाकर्ताओं को नियम 13.8 के तहत हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन साथ ही यह भी अनुरोध किया गया था कि *तदर्थ* पदोन्नति के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने उच्च पद धारण करने का अधिकार हासिल नहीं किया था। वी. के. झांजी, जे ने प्रतिवादियों की इस दलील को स्वीकार कर लिया और *रिशाल सिंह के मामले* (सुप्रा) में शीर्ष अदालत के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता के दावे को बरकरार रखा। **जगत सिंह बनाम *हरियाणा राज्य* 1995** (2) आर.एस.जे. 229 मामले में वीके झांजी, जे. ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था ।

(15) हमें ऐसा प्रतीत होता है कि न तो शीर्ष अदालत के समक्ष और न ही झांजी, जे. के समक्ष, प्रतिवादियों ने मामले को सही परिप्रेक्ष्य में पेश किया था और शीर्ष अदालत और झांजी के ध्यान में नहीं लाया था कि याचिकाकर्ता नियम 13.8 (2) के तहत पदोन्नति के लिए अयोग्य थे क्योंकि उन्हें नियम 13.5 के तहत चयन ग्रेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था।

(16) यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इसी तरह का मुद्दा वीके झांजी, जे. *के समक्ष* सीडब्लूपी नंबर 592/93, नाहर सिंह बनाम *हरियाणा राज्य* में *भी उठा* था। 6 नवंबर, 1995 के अपने आदेश द्वारा, झांजी, जे. ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता की पदोन्नति को नियम 13.8 के तहत 10 प्रतिशत रिक्तियों के खिलाफ नहीं माना जा सकता है और इसलिए, याचिकाकर्ता का प्रत्यावर्तन, जो केवल एक *तदर्थ* हेड कांस्टेबल था, किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं था। अपने नवीनतम फैसले में, वीके झांजी, जे ने *हरदेन सिंह के मामले* (उपर्युक्त) *और* जगत सिंह के मामले (उपर्युक्त) में अपने पहले के फैसलों को अलग किया।

(17) सीडब्ल्यूपी संख्या 11747/95 में *सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य ने* 2 मई, 1996 और सीडब्ल्यूपी संख्या 18192/94 पर निर्णय लिया। एच. सी. सुरिंदे सिंह बनाम *हरियाणा राज्य* का निर्णय 8 मई 1996 को लिया गया (दोनों खंडपीठ द्वारा) *रिशाल सिंह के मामले* (उपर्युक्त) *में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और* हरदेन सिंह के मामले (उपर्युक्त) *में विद्वान एकल न्यायाधीश के* निर्णय पर विचार किया गया है।

(18) याचिकाकर्ता के मामले में, रिकॉर्ड से यह साबित हो गया है कि याचिकाकर्ता को नियम 13.5 के साथ नियम 13.बी के तहत चयन ग्रेड कांस्टेबल के रूप में कभी पदोन्नत नहीं किया गया था और वह 5 जुलाई, 1989 को चयन ग्रेड कांस्टेबल नहीं था, जिस तारीख को पुलिस उप महानिरीक्षक ने उसे तदर्थ हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत करने का आदेश जारी किया था। मामले के रिकॉर्ड से यह भी स्थापित होता

है कि आदेश अनुलग्नक पी 4 जारी होने से पहले न तो पुलिस अधीक्षक, रेलवे और न ही पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे और संचालन ने हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों के मामलों की जांच और विचार किया था। इसलिए, यह मानना उचित है कि याचिकाकर्ता की पदोन्नति नियम 13.8 (2) के तहत नहीं थी और उसे वरिष्ठ व्यक्तियों के दावों की अनदेखी करते हुए आकस्मिक पदोन्नति दी गई थी और इस तरह की पदोन्नति के आधार पर याचिकाकर्ता हेड कांस्टेबल के रूप में बने रहने के लिए किसी भी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और न ही वह केवल इस आधार पर पुष्टि का दावा कर सकता है कि उसने दो साल से अधिक की अवधि के लिए हेड कांस्टेबल का पद संभाला था।

(19) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि लागू आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है और प्रतिवादियों पर पात्र वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए जगह बनाने के लिए याचिकाकर्ता को कांस्टेबल के पद पर वापस लाने में मनमाने ढंग से काम करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। नतीजतन, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। लागत आसान हो गई।

*जे.एस.टी.*

16664 एच.सी. - गवर्नमेंट प्रेस, यू.टी., चंडीगढ़।

**अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**खुश करण जोत सिंह गिल**
**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**
**चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी**